NYCS
RNI: DELBIL/2008/25219, ₹20

युवा सहकार

www.nycsindia.com
अप्रैल 2025, नई दिल्ली

सहकारी शिक्षा में पारंगत होंगे युवा

अंदर के पन्नों पर:

- त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल पारित
- सहकारी बैंकों पर बढ़ा भरोसा

Did You Know?

2025 is the International Year of Cooperatives!

The UN declared 2025 as a year to celebrate cooperatives around the world. Cooperatives are businesses owned by their members, focusing on both profit and the needs of their communities. They play a big role in sustainable development and achieving the UN's Sustainable Development Goals by 2030.

There will be a year-long celebration to raise awareness about cooperatives and their positive impact.

युवा सहकार

वर्ष : 01, अंक-10, अप्रैल-2025

निदेशक मंडल
एनवाईसीएस

प्रकाश चंद्र साहू
मनीष कुमार
राजेश बाबूलाल पांडे
प्रकृति क्षितिज पंड्या
बालू गोपालकृष्णन
ज्योतिर्मय सिंह महतो
गौरव पांडेय
हिरेन मधुसूदन शाह
राघव गर्ग
आशुतोष सतीश गुप्ता

कार्यालय

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस)
209, द्वितीय तल, ए2बी, वर्द्धमान जनक मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058
मोबाइल नंबर : 9205595944
लैंडलाइन नंबर : 011-45096652/40153681
E-mail: nycs.ltd@gmail.com
Web: www.nycsindia.com

Registration No
DELBIL/2008/25219

संकल्पना, कंटेंट व डिजाइन : फार्च्यूना कम्यूनिकेशंस प्रा. लि., नई दिल्ली

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित एवं जीएम ऑफसेट, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-92 द्वारा मुद्रित।

अभिषेक कुमार: पीआरबी एक्ट के तहत खबरों के चयन के उत्तरदायी।

NYCSIndia

सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण को मिलेगी मजबूती 04
नैनो उर्वरकों से इफको हुई समृद्ध 05

06 सहकारी शिक्षा में पारंगत होंगे युवा

16 यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही कोऑपरेटिव से जुड़ेंगे युवा

पीएम इंटर्नशिप: ऐप से भी आवेदन 19
बीज अनुसंधान में क्रांति लाएगी इफको 20
सहकारिता में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर 22
स्टार्टअप कंपनियों से ज्यादा बेहतर करने की उम्मीद 26
स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करने पर फोकस 29
एनवाईसीएस ने अंकिता की उम्मीदों को किया रौशन 30

सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण को मिलेगी मजबूती

यह वर्ष अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। ऐसे में सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना बहुत मायने रखती है। यह यूनिवर्सिटी कौशल आधारित प्रशिक्षण, अनुसंधान और नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित कर युवाओं को सशक्त करने के अलावा सहकारी क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देगी।

सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए देश में पहली बार सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। देश में सहाकारिता की नींव रखने वालों में शुमार त्रिभुवन दास किशिभाई पटेल के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। आज जिस गुजरात राज्य सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीएससीएमएमएफ) को पूरी दुनिया अमूल के नाम से जानती है, वह त्रिभुवन दास पटेल के विचारों की ही देन है। गुजरात के आणंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (इरमा) के परिसर में बनने वाले इस विश्वविद्यालय को संसद की मंजूरी मिल चुकी है। इरमा की स्थापना 1979 में ग्रामीण उत्पादकों के संगठनों के प्रबंधन को पेशेवर बनाने के लिए की गई जिसका सबसे ज्यादा फायदा डेयरी उद्योग और डेयरी सहकारी समितियों को हुआ। यह देश में दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के दिमाग की उपज थी। आज डेयरी उद्योग और सहकारिता क्षेत्र में इस संस्थान से निकले हजारों कुशल प्रबंधक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब इसे यूनिवर्सिटी का रूप दिया जा रहा है जो देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह की सोच की देन है।

इससे न सिर्फ सहकारिता क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी, बल्कि सहकारिता क्षेत्र में वर्तमान में काम कर रहे लोगों को भी बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जा सकेगा। अभी सहकारिता क्षेत्र में डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, पीएचडी आदि करने की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ ही, सहकारिता क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण देने की भी सुविधा सीमित है। यूनिवर्सिटी के बन जाने से इन सुविधाओं को बढ़ाने में सहूलियत मिलेगी। सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण से युवाओं में दक्षता व क्षमता निर्माण करने के साथ-साथ सहकारी नवाचार और अनुसंधान में भी तेजी आएगी जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हर साल 8 लाख लोग सहकारिता में शिक्षित एवं प्रशिक्षित होंगे।

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) भी अपनी स्थापना के समय से ही विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यमों से युवाओं को प्रशिक्षण देती आई है। युवाओं को कौशल एवं उद्यमिता विकास, स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से रोजगारोन्मुखी और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए युवा सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने में इस संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है। एनवाईसीएस ने अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण दिया है। सहकारी यूनिवर्सिटी बन जाने के बाद एनवाईसीएस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी तेजी आने की संभावना है।

यह वर्ष अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में भी मनाया जा रहा है। ऐसे में सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए किया गया यह बड़ा सुधार बहुत मायने रखता है। यह यूनिवर्सिटी कौशल आधारित प्रशिक्षण, अनुसंधान और नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित कर युवाओं को सशक्त करने के अलावा सहकारी क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। यहां से निकले कुशल पेशेवर देश की सहकारी संस्थाओं को नई दिशा देंगे जिससे 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय सहकारिता आंदोलन की धाक जमाने में मदद मिलेगी।■

प्रकाश चंद्र साहू
अध्यक्ष, नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड

नैनो उर्वरकों से इफको हुई समृद्ध

युवा सहकार टीम

2024-25 में नैनो उर्वरकों की बिक्री 47 प्रतिशत बढ़ी, नैनो डीएपी की बिक्री में 118 प्रतिशत का आया उछाल

इफको नैनो एनपीके भी आएगा जिससे फसल उत्पादकता बढ़ेगी और पोषक तत्वों की घटेगी हानिः डॉ. उदय शंकर अवस्थी

दुनिया की नंबर एक कोऑपरेटिव इफको के लिए नैनो उर्वरक वरदान साबित हो रहे हैं। इसकी बदौलत न सिर्फ मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिल रही है, बल्कि उर्वरकों का आयात बिल घटाने के साथ ही इफको का मुनाफा बढ़ाने में भी यह मददगार है। इसके अलावा, नैनो उर्वरकों के बढ़ते उपयोग और रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल घटने से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आई है। इफको इस कमी के प्रमाणीकरण संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण की संभावना तलाश रहा है। टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने में नैनो उर्वरकों का उपयोग सकारात्मक कदम सिद्ध हुआ है। इससे पैदावार बढ़ी है जो भारत की अर्थव्यवस्था के साथ ही किसानों के लिए भी फायदेमंद है। इसे ध्यान में रखते हुए इफको अब नैनो एनपीके भी लाने जा रहा है। अभी नैनो तकनीक से नैनो यूरिया (तरल) और नैनो डीएपी (तरल) का उत्पादन हो रहा है। ये दोनों उर्वरक खेती में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं।

इफको के नैनो उर्वरकों का देश में नहीं, विदेशी किसान भी इसका उपयोग कर रहे हैं। अभी 40 देशों को इसका निर्यात किया जा रहा है। इफको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने कहा है, 'इफको मिट्टी में प्रयोग होने वाले दानेदार नैनो एनपीके उर्वरक भी लाने जा रहा है। इस दानेदार नैनो एनपीके उर्वरक में मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक और कॉपर प्रचुर मात्रा में हैं जिनसे फसल उत्पादकता बढ़ेगी और पोषक तत्वों की हानि भी कम होगी। यह नया उत्पाद नैनो यूरिया (तरल) व नैनो डीएपी (तरल) के साथ मिलकर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त कर सकता है। इससे प्राथमिक पोषक तत्वों की उच्च उपयोग दक्षता के साथ संतुलित पोषण को भी बढ़ावा मिलेगा। नैनो तकनीक, ड्रोन तकनीक, एआई तकनीकों को शामिल करके हम देश की कृषि और खाद्य मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। इफको के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, मार्केटिंग टीम की प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत के कारण ही यह संभव हुआ है।'

उन्होंने बताया कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों से इफको के मुनाफे में वृद्धि का रुझान जारी है। यह वृद्धि नैनो उर्वरकों की बिक्री पर इफको के बढ़ते प्रोत्साहन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2024-25 में नैनो उर्वरकों की बिक्री में 47 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। इसकी बदौलत पूरे वित्त वर्ष में इफको का कर पूर्व मुनाफा 3,000 करोड़ रुपये के पार होने की उम्मीद है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के समर्थन से नैनो उर्वरक इफको के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा है। व्यापक जागरूकता अभियान और अनुसंधान ने इस फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसायटी को किसानों के बीच उत्पादों की स्वीकार्यता बढ़ाने में मदद की है।

आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024-25 में नैनो उर्वरकों की 365 लाख बोतलें बेची गई। इनमें से 268 लाख बोतलें इफको नैनो यूरिया प्लस (लिक्विड) और 97 लाख बोतलें इफको नैनो डीएपी (लिक्विड) की बेची गई। वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में इफको नैनो यूरिया प्लस (लिक्विड) की बिक्री 31% और इफको नैनो डीएपी (लिक्विड) की बिक्री 118% अधिक है। यह बिक्री मात्रा 12 लाख टन पारंपरिक यूरिया और 4.85 टन पारंपरिक डीएपी के बराबर है। वित्त वर्ष 2023-2024 में नैनो उर्वरकों की कुल 249 लाख बोतलें बेची गई थी।

अपने संदेश में डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान इफको ने 1 जुलाई, 2024 से एक राष्ट्रव्यापी 'मॉडल नैनो विलेज/क्लस्टर परियोजना' शुरू की है। इसके तहत 2000 एकड़ में फैले 203 गांव समूहों का चयन किया गया है, जो फसल उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि के साथ थोक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए नैनो उर्वरकों को अपनाने में अग्रणी हैं। उन्होंने बताया कि 5 लाख एकड़ को कवर करने वाले नैनो विलेज पोर्टल में 90,000 से अधिक किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से 40,000 किसानों ने इफको नैनो उर्वरकों और सागरिका की 5.30 लाख से अधिक बोतलें खरीदी हैं और 72,000 एकड़ में एग्री ड्रोन द्वारा इनका छिड़काव किया है। इस परियोजना के कारण रासायनिक उर्वरक के उपयोग में 28.73% की कमी आई और फसल की पैदावार में 5.80% की वृद्धि हुई।

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025 संसद से पारित

सहकारी शिक्षा में पारंगत होंगे युवा

सहकारिता क्षेत्र में कुशल पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मिलेगी मदद, अगले पांच वर्ष में 17 लाख प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत का अनुमान

सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण से युवाओं में दक्षता व क्षमता निर्माण करेगा नया विश्वविद्यालय

सहकारी नवाचार और अनुसंधान में आएगी तेजी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती

युवा सहकार टीम

वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने की केंद्र सरकार की विभिन्न पहलों से इस क्षेत्र में कुशल पेशेवरों, नवाचार और नई रणनीतियों की मांग बढ़ी है। इसे पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे संस्थान की जरूरत महसूस की जा रही थी जो न सिर्फ सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा दे सके, बल्कि सहकारी संगठनों की कार्यक्षमता में सुधार, कुशल पेशेवरों से पारदर्शिता को बढ़ावा, डिजिटल नवाचार के तहत सहकारी प्लेटफार्मों पर अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय मानकों पर सहकारी संस्थानों का निर्माण और नई योजनाओं के विकास के लिए वित्तीय रणनीतियों का सृजन जैसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को सफल बनाने में मददगार हो। इसी को ध्यान में रखते हुए देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय बनाने की संकल्पना की गई। इसके लिए संसद के बजट सत्र के पहले चरण में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल,

2025 पेश किया गया जिसे सत्र के दूसरे चरण में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस बिल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर करते ही यह कानून बन जाएगा जिसके बाद यूनिवर्सिटी के निर्माण का कार्य शुरू हो सकेगा।

गुजरात के आणंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (इरमा) के परिसर में बनने वाले इस केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम भारत में सहकारिता की नींव रखने वाले व्यक्तियों में शुमार त्रिभुवन दास किशिभाई पटेल के नाम पर रखा गया है। आज जिस गुजरात राज्य सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जीसीएमएमएफ) को हम सब अमूल के नाम से जानते हैं, वह त्रिभुवन दास पटेल के विचारों की ही देन है। इसके निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये का शुरूआती प्रावधान किया गया है। यह वर्ष अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ऐसे में यूनिवर्सिटी की स्थापना का यह कदम और ज्यादा महत्व रखता है। यह सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार है यह विश्वविद्यालय कौशल आधारित प्रशिक्षण, अनुसंधान और नेतृत्व विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा जिससे युवाओं को सशक्त किया जा सकेगा और सहकारी क्षेत्र में सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सकेगा। इससे सहकारी क्षेत्र में समग्र शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध के नए अवसर मिलेंगे। सहकारी क्षेत्र में नवीनतम शैक्षिक दृष्टिकोण अपनाकर यह यूनिवर्सिटी प्रशिक्षित पेशेवरों को तैयार करेगी जिससे देशभर में सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार आएगा। मानव संसाधन की दक्षता बढ़ने के साथ देशभर में सहकारिता के क्षेत्र में दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों और संस्थागत सुधारों का सशक्त नेटवर्क स्थापित होगा।

संसद द्वारा विधेयक पारित किए जाने पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार प्रकट करते हुए कहा, ‘यह विधेयक देश में सहकार, नवाचार और रोजगार की त्रिवेणी लाएगा। अब सहकारी शिक्षा भारतीय शिक्षा व पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनेगी और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से देशभर के प्रशिक्षित युवा सहकारी क्षेत्र को अधिक व्यापक, सुव्यवस्थित और आधुनिक युग के अनुकूल बनाएंगे।’ राज्यसभा ने 1 अप्रैल को इस बिल को पारित किया, जबकि लोकसभा में यह बिल 26 फरवरी को पारित हुआ। अमित शाह ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा, ‘त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ सहकारिता क्षेत्र

डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जैसे कोर्स कर पाएंगे युवा, पीएचडी भी कर सकेंगे, हर साल 8 लाख लोग होंगे प्रशिक्षित

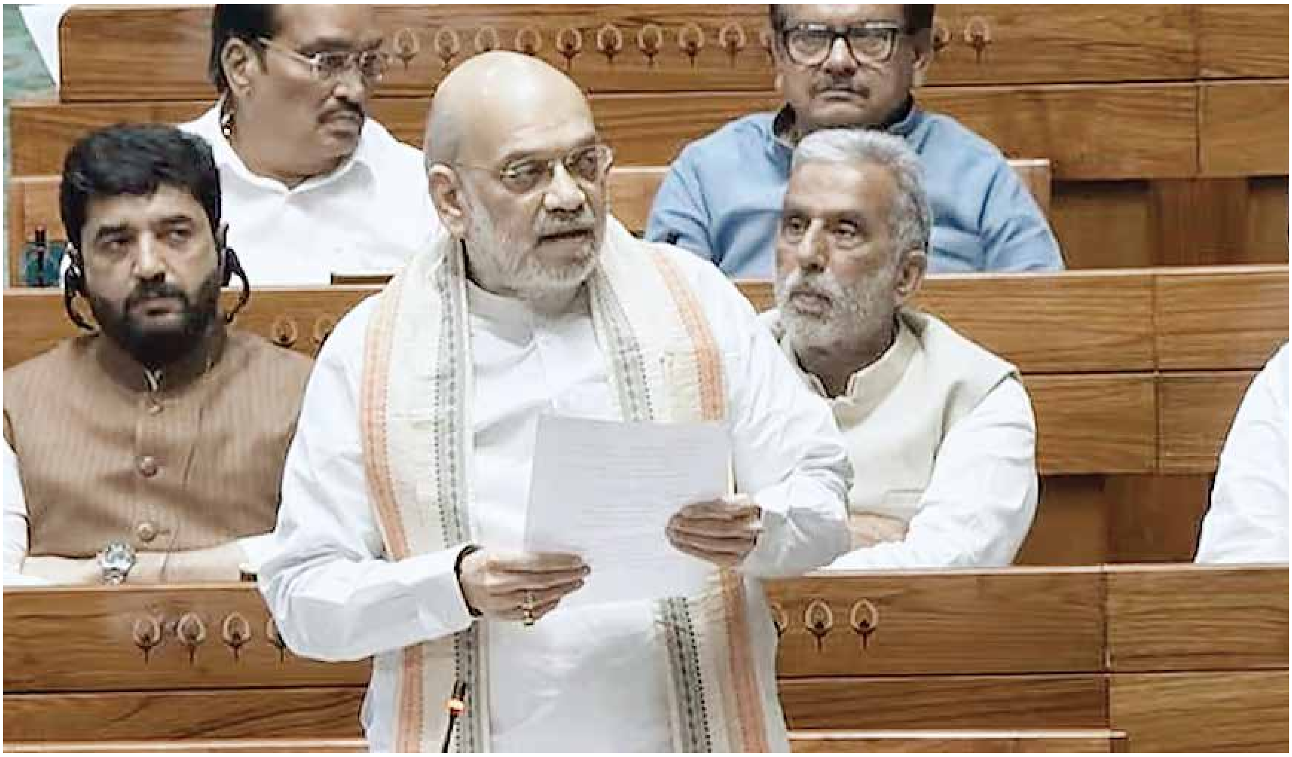

“यह विधेयक देश में सहकार, नवाचार और रोजगार की त्रिवेणी लाएगा। अब सहकारी शिक्षा भारतीय शिक्षा व पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनेगी और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से देशभर के प्रशिक्षित युवा सहकारी क्षेत्र को अधिक व्यापक, सुव्यवस्थित और आधुनिक युग के अनुकूल बनाएंगे।”

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। इस विश्वविद्यालय से प्रति वर्ष 8 लाख लोग प्रशिक्षित होंगे। इसमें शार्ट और लॉन्ग टर्म कोर्स करने वालों के अलावा चंद दिनों या हफ्ते भर तक चलने वाले ट्रेनिंग कोर्स भी शामिल होंगे। इससे पूरे देश को सहकारिता की भावना और आधुनिक शिक्षा से युक्त युवा सहकारी नेतृत्व मिलेगा। कोऑपरेटिव क्षेत्र के विकास और विस्तार को देखते हुए प्रशिक्षित मानव संसाधन की जरूरत है। यह यूनिवर्सिटी इस जरूरत को पूरा करने का काम करेगी। यहां से डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त युवाओं को सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं और कंपनियों में नौकरी मिलेगी।' उनके मुताबिक, इस यूनिवर्सिटी से भारत ग्लोबल वैल्यू चैन में भी बड़ा योगदान दे सकेगा। न्यू एज कोऑपरेटिव कल्चर भी इस यूनिवर्सिटी से शुरू होगा।

राज्यसभा में इस बिल पर हुई चर्चा का जवाब केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने दिया। मोहोल ने कहा, 'सहकारिता क्षेत्र में गतिशीलता लाने और इसके विस्तार के लिए एक संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है। इसी उद्देश्य से त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है। कई सहकारी संस्थाओं में कार्य क्षमता की कमी, मैनेजमेंट में अनियमितताएं और तकनीकी संसाधनों के सीमित उपयोग जैसी चुनौतियां हैं जिससे उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से सहकारिता क्षेत्र का दायरा और प्रभाव बढ़ेगा, जिससे नए स्वरोजगार और नवाचार के अवसर सृजित होंगे। आज पैक्स के सचिव से लेकर एपेक्स बैंक के एमडी तक, सभी स्तरों पर कार्य कुशलता और अनुशासन के लिए योग्य प्रशिक्षण की आवश्यकता है। एक अनुमान के अनुसार, आगामी पांच वर्षों में सहकारिता क्षेत्र को लगभग 17 लाख प्रशिक्षित युवाओं की जरूरत होगी। इस आवश्यकता को देखते हुए यूनिवर्सिटी की स्थापना की पहल की गई है।'

उन्होंने कहा कि फिलहाल सहकारिता क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है और यह बिखरी हुई भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के

नेतृत्व और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना का निर्णय लिया गया। यह यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता पूरा कर देश के युवाओं में कोऑपरेटिव स्पिरिट विकसित करेगी और उन्हें इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी।

देशभर में अभी सैकड़ों की संख्या में सहकारी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान हैं, मगर किसी के पाठ्यक्रम में समानता नहीं है। न ही ये किसी एकीकृत राष्ट्रीय संस्थान से संबद्ध हैं। सहकारिता मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी बनने से पहले ही कोऑपरेटिव क्षेत्र की जरूरत को ध्यान में रख कर कोर्स डिजाइन का काम कर दिया है। इस यूनिवर्सिटी में डिग्री, डिप्लोमा कोर्स के अलावा पीएचडी की डिग्री भी दी जाएगी। साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे मौजूदा कर्मचारियों के लिए एक सप्ताह का सर्टिफिकेट कोर्स भी होगा। यूनिवर्सिटी बनने के एक साल के भीतर देश के लगभग हर जिले में इससे जुड़े कॉलेज खोले जाएंगे या पहले से मौजूद शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को इससे संबद्ध किया जाएगा। इसके माध्यम से सहकारी सिद्धांतों और सहकारी गतिविधियों का विस्तार होगा, कोऑपरेटिव क्षेत्र को नई प्रौद्योगिकी का फायदा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। साथ ही, अनुसंधान और नवाचार भी बढ़ेंगे और जमीनी स्तर पर कोऑपरेटिव क्षेत्र मजबूत होगा। इस यूनिवर्सिटी को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा।

वर्तमान में सहकारी शिक्षण में एकरूपता का अभाव है। डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि, बैंकिंग और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट प्रदान करके यह विश्वविद्यालय सहकारी शिक्षा को सुव्यवस्थित करेगा। छात्रों, सहकारी समिति के सदस्यों और उद्योग के पेशेवरों को सशक्त बनाने के लिए भी इसमें विशेष पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यह पहल मौजूदा ज्ञान अंतराल को पाटने और वैश्विक स्तर पर भारत के सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगी। इस पहल की एक प्रमुख विशेषता प्राचीन ज्ञान और आधुनिक शिक्षा का मिश्रण होगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

वैश्विक सहकारिता में भारत की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक है। सहकारी क्षेत्र परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो क्षमता और संभावनाओं से भरा हुआ है। अनुमान है कि वर्ष 2030 तक सहकारी समितियों में 5.5 करोड़ प्रत्यक्ष रोजगार और 5.6 करोड़ अतिरिक्त स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता होगी। इससे रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत होगी। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना

सहकारी शिक्षण संस्थानों के बीच बनेगा सेतु

इस विश्वविद्यालय में डेयरी, मत्स्य, चीनी, बैंकिंग, ग्रामीण ऋण, सहकारी वित्त, सहकारी मार्केटिंग और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को पाठ्यक्रम में खासतौर पर प्रमुखता दी जाएगी। जिन राज्यों में सहकारी संस्थाओं की अधिकता है उनमें चार से पांच कॉलेजों को सहकारी विश्वविद्लाय से संबद्ध किया जाएगा और बाकी राज्यों में एक से दो सहकारी कॉलेज इससे संबद्ध किए जाएंगे। इसे वैश्विक स्तर के सहकारी विश्वविद्यालयों और सहकारी संस्थानों से भी संबद्ध किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह देशभर में सहकारी प्रबंधन संस्थानों को जोड़ने की एक कड़ी के रूप में काम करेगा। सहकारी संस्थाओं के अलग-अलग प्रशिक्षण और प्रबंधन डिप्लोमा व डिग्री कार्यक्रमों का डिटेल तैयार कर लागू करेगा। इसमें पारंपरिक भारतीय आर्थिक दर्शन को समकालीन प्रबंधन तकनीकों के साथ एकीकृत किया जाएगा। वैदिक परंपराओं से प्रेरित होकर छात्र इसमें स्थायी कृषि पद्धतियों, नैतिक व्यावसायिक आचरण और समुदाय-संचालित आर्थिक मॉडल के बारे में सीखेंगे। इस विश्वविद्यालय का एक अन्य उद्देश्य पूरे भारत में सहकारी शिक्षा को मानकीकृत करना है। सहकारी विश्वविद्यालय एक केंद्रीय संस्थान के रूप में भी कार्य करेगा, जो आईसीएआर केंद्रों, कृषि विज्ञान केंद्रों, सीएसआईआर संस्थानों, स्वास्थ्य संबंधी संस्थानों और अन्य विश्वविद्यालयों से संसाधनों को एकत्रित करेगा। यह पैक्स सचिवों को प्रशिक्षित करेगा और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों का समर्थन करेगा। इससे सहकारी विकास के लिए बहु-विषयक दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। पारंपरिक एमएसपी मॉडल से आगे बढ़ाते हुए यह विश्वविद्यालय सहकारी समितियों को बाजार-संचालित समाधान और आत्मनिर्भर व्यवसाय मॉडल अपनाने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह विश्वविद्यालय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए सहकारी मॉडल विकसित करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों के साथ मिलकर काम करेगा, जिससे सस्ती चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित होंगी।

सहकारिता क्षेत्र में गतिशीलता लाने और इसके विस्तार के लिए एक संस्थागत व्यवस्था आवश्यक है। यह यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता पूरा कर देश के युवाओं में कोऑपरेटिव स्पिरिट विकसित करेगी और उन्हें इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगी।

मुरलीधर मोहोल
केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र के लिए योग्य और प्रशिक्षित पेशेवर प्रदान करने के लिए सहकारी शिक्षा का मानकीकरण और उन्नत करने के लिए अपने स्वयं के स्कूल और संबद्ध संस्थान स्थापित करेगा। सहकारी कर्मचारियों, बोर्ड के सदस्यों और अन्य हितधारकों के बीच क्षमता का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य है।

से मानव संसाधन की इस बड़ी मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहकार से समृद्ध भारत की जो नींव रख रहे हैं, उसमें सहकारी विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना से क्षेत्रीय क्षमता निर्माण, सहकारी जागरूकता, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और विस्तार गतिविधियों को महत्व मिलेगा। विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय सलाहकार निकाय के रूप में भी काम करेगा, सहकारी समितियों का मार्गदर्शन करेगा और सर्वोत्तम प्रथाओं, सरकारी योजनाओं और नियामक परिवर्तनों पर परामर्श सेवाएं प्रदान करेगा। यह विश्वविद्यालय सहकारी शिक्षा को नई दिशा प्रदान करेगा। यह सहकारी समितियों को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख माध्यम के रूप में स्थापित करेगा। यह वैश्विक सहकारी मॉडल, सहकारी समितियों में ब्लॉकचेन और मेंटरशिप और फंडिंग पहलों के माध्यम से सहकारी उद्यमिता को बढ़ाने की रणनीतियों पर शोध करेगा। सहकारी क्षेत्र की शिक्षा, विस्तार, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श आवश्यकताओं को पूरा करने में यह निर्णायक भूमिका निभाएगा। इसका उद्देश्य ज्ञान और व्यवहार के बीच की खाई को पाटते हुए एक गतिशील संस्थान के रूप में काम करना और युवाओं को सहकारी उद्यमों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करना है।

सहकारिता की दूरस्थ शिक्षा होगी मजबूत

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र के लिए योग्य और प्रशिक्षित पेशेवर प्रदान करने के लिए सहकारी शिक्षा का मानकीकरण और उन्नत करने के लिए अपने स्वयं के स्कूल और संबद्ध संस्थान स्थापित करेगा। सहकारी कर्मचारियों, बोर्ड के सदस्यों और अन्य हितधारकों के बीच क्षमता का निर्माण करना भी इसका उद्देश्य है। यह सहकारी शिक्षा के पूरे क्षेत्र में शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा। यह दूरस्थ शिक्षा पर जोर देते हुए अंतःविषय और अत्याधुनिक तकनीक सीखने के अवसर प्रदान करेगा और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाएगा।

मोदी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) का 50 प्रतिशत सहकारी क्षेत्र से उत्पन्न करने का है। अनुसंधान, प्रशिक्षण और नीतिगत पहल के माध्यम से यह मानव संसाधनों को विकसित करेगा जो उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, रोजगार पैदा करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे सकेंगे। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को आगे बढ़ाकर और पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों की ओर संचारित करके सहकारिता विश्वविद्यालय सहकारी समितियों को

दीर्घकालिक स्थिरता के लिए तैयार करेगा। हरित प्रौद्योगिकियों, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और समावेशी शासन को प्रोत्साहित करते हुए यह पहल भारत को सतत सहकारी विकास में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगी। विश्वविद्यालय का एक प्रमुख लक्ष्य किसानों और कारीगरों के आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित करके राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना है। वास्तव में किसान और कारीगर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और सहकारी माध्यम से उनकी समृद्धि से राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बल मिलेगा।

अभी राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की जिम्मेदारी नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग (एनसीसीटी) पर है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके नेटवर्क में 20 संस्थान हैं जो दो तरह के हैं। एक है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट (आरआईसीएम), जो एक से अधिक राज्यों को देखते हैं। आरआईसीएम 5 हैं। दूसरा है आईसीएम (इंस्टीट्यूट ऑफ कोपरेटिव मैनेजमेंट) जो 14 राज्यों में है। यह मूलतः उसी राज्य में शिक्षण-प्रशिक्षण का काम देखता है जहां स्थित है। इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान पुणे में है जिसका नाम वैमनीकॉम (वैंकुठ लाल मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट) है। यह कई तरह के कोर्स चलाता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कोर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय में डायरेक्टर और एनसीसीटी के पूर्व डायरेक्टर कपिल मीणा ने 'युवा सहकार' को बताया, 'एनसीसीटी और इसके इंस्टीट्यूट सालाना करीब तीन लाख लोगों को ही ट्रेनिंग दे पाते हैं। इनमें सदस्यों के जागरूकता कार्यक्रम जो एक या दो दिन के होते हैं से लेकर लॉन्ग टर्म कोर्स भी हैं। सहकारिता विश्वविद्यालय बनने से सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। एग्रीकल्चर में बीएससी, एमएससी के कोर्स हैं, पीचडी भी की जाती है। मगर कोऑपरेटिव में इस तरह के कोई कोर्स नहीं हैं। अभी एग्रीक्लचर के साथ ही कोऑपरेटिव को पढ़ाया जाता है। यूनिवर्सिटी के आने से कोऑपरेटिव पर डेडिकेटेड कोर्स बनना शुरू होंगे। छात्र एमफिल, पीएचडी, एमबीए आदि कर सकेंगे। यह यूनिवर्सिटी का काम होगा कि अलग-अलग कोर्स डिजाइन करें और उन्हें विभिन्न संस्थाओं में शुरू करे। एनसीसीटी और इसके 20 संस्थान भी यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगे। यह हब एंड स्पोक मॉडल पर चलेगा यानी यूनिवर्सिटी हब का काम करेगी और विभिन्न संस्थान उससे संबद्ध होंगे। सहकारिता बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसमें 30 अलग-अलग सेक्टर में काम हो रहा है। इनमें डेरी, फिशरीज, कृषि या हाउसिंग जैसे कई सेक्टर शामिल हैं। यूनिवर्सिटी बनने से इन सबके लिए अलग-अलग कोर्स उपलब्ध होंगे जिनमें शिक्षित-प्रशिक्षित होकर युवा अपना

इरमा की स्वायत्तता रहेगी बरकरार

आणंद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रुरल मैनेजमेंट (इरमा) की स्थापना वर्ष 1979 में की गई थी। 60 एकड़ में फैले इरमा को अस्तित्व में लाने में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी), स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, गुजरात सरकार और इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन का विशेष योगदान रहा है। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की भूमिका अहम रही है। यहां से निकलने वाले प्रबंधकों की युवा खेप देश के विभिन्न संस्थानों को संभाल रही है। इस संस्थान की उपयोगिता को देखते हुए ही इसे सहकारिता विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय किया गया। इरमा को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2025 जब प्रभावी हो जाएगा, तो इरमा सोसायटी भंग कर दी जाएगी। इरमा नए विश्वविद्यालय के स्कूलों में से एक बन जाएगा और इसे ग्रामीण प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया जाएगा। इसकी स्वायत्तता और पहचान विश्वविद्यालय के संस्थागत ढांचे के भीतर संरक्षित की जाएगी।

अभी राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण की जिम्मेदारी एनसीसीटी पर है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसके नेटवर्क में 20 संस्थान हैं जो दो तरह के हैं। एक है आरआईसीएम, जो एक से अधिक राज्यों को देखते हैं। दूसरा है आईसीएम जो 14 राज्यों में है।

> **सहकारिता मंत्रालय एजुकेशन और ट्रेनिंग पर एक नई स्कीम लाने पर भी काम कर रहा है। इससे बड़ी संख्या में सहकारी क्षेत्र के लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी।**

करियर बना सकेंगे। सहकारिता की पॉलिसी बनाने में सरकार को इनपुट देने का काम भी यूनिवर्सिटी करेगी। सहकारिता मंत्रालय एजुकेशन और ट्रेनिंग पर एक नई स्कीम लाने पर भी काम कर रहा है। इससे बड़ी संख्या में सहकारी क्षेत्र के लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकेगी। यूनिवर्सिटी के शुरू हो जाने के बाद इस स्कीम को लाने की योजना है।'

स्कूलों में भी पढ़ाई जाए सहकारिताः चंद्रपाल यादव

देश की प्रमुख फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कृभको के चेयरमैन चंद्रपाल सिंह यादव ने 'युवा सहकार' से बातचीत में कहा, 'हमने सरकार को सुझाव दिया है कि कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी की स्थापना के अलावा कोऑपरेटिव का एक चैप्टर स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए ताकि सहकारिता की बुनियादी बातों से बच्चों को अवगत कराया जा सके। इसे एग्रीकल्चर वाले पाठ्यक्रम में जोड़ा जा सकता है ताकि उन्हें इसका बुनियाद ज्ञान हो सके।

इससे उनमें सहकारिता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और इसका ज्ञान स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इस देश के हर व्यक्ति को इसका ज्ञान होना चाहिए और इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। कोऑपरेटिव में रोजगार के नए-नए अवसर पैदा करने की असीमित क्षमता है जिसका फायदा युवा उठा सकते हैं।■

शुरू होगी सहकारी टैक्सी सेवा

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक, 2025 पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा को बताया कि अगले कुछ महीनों में सहकारिता मॉडल पर एक टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। इसमें दोपहिया वाहन, ऑटो रिक्शा और चौपहिया वाहनों का पंजीकरण हो सकेगा। सहकार से समृद्धि के सिद्धांत पर सहकारी टैक्सी सेवा इच्छुक टैक्सी चालकों द्वारा बनाई जाएगी जिसका प्रबंधन उसके सदस्यों के पास होगा। इस पहल का उद्देश्य सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से लोकतांत्रिक प्रबंधन सुनिश्चित करना और ऐसी सहकारी टैक्सी सोसायटी द्वारा अर्जित लाभ को सदस्य टैक्सी चालकों के बीच समान रूप से वितरित करना है। अमित शाह ने कहा कि सहकारिता एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें लोग स्वेच्छा से एकत्रित होकर एक सहकारी समिति बनाते हैं, जो आपसी लाभ और समान आर्थिक हितों पर आधारित होती है। आर्थिक सहयोग का सहकारी मॉडल सदस्यों के लिए अधिक लाभकारी साबित हुआ है।

युवाओं को प्रशिक्षित कर रही एनवाईसीएस

युवा सहकार टीम

युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से संबंधित गतिविधियों में प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (एनवाईसीएस) विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है। इसका उद्देश्य युवाओं को आर्थिक रूप से उत्पादक बनाने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से रोजगारोन्मुखी और आय सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए युवा सशक्तिकरण को सुनिश्चित किया जाता है। एनवाईसीएस ने अपनी स्थापना के 26 वर्षों में डेढ़ लाख से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी आजीविका के माध्यम को सुनिश्चत किया है।

एनवाईसीएस मल्टी स्टेट, मल्टी पर्पज कोऑपरेटिव सोसायटी है जो युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने की दिशा में काम करती है। युवाओं की इस कोऑपरेटिव सोसायटी की मुख्य गतिविधियों में माइक्रो फाइनेंसिंग, युवाओं को सुविधा उपलब्ध कराना, स्वयं सहायता समूह बनाना, उद्यमिता विकास और युवाओं एवं अन्य हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना शामिल है ताकि उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। अपनी स्थापना के बाद से ही एनवाईसीएस पूरे देश में उद्यमिता विकास और युवाओं को उद्यमी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्हें मार्केटिंग स्किल, सॉफ्ट स्किल, मैनेजमेंट स्किल, टीम प्रबंधन, नेतृत्व प्रबंधन और जीवन कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। एनवाईसीएस विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियां संचालित करती है।

सीएसआर प्रोजेक्टः एनवाईसीएस-कोविडा ने बाबासाहेब अंबेडकर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (बार्टी), महानगर गैस लिमिटेड, महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के साथ विभिन्न सीएसआर परियोजनाएं शुरू की हैं। इन परियोजनाओं के तहत वित्त वर्ष 2023-24 तक 4,500 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया है।

पीएमकेवीवाईः एनवाईसीएस राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण भागीदार है। भारतीय युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार कौशल प्रशिक्षण देने के लिए यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है। इससे उन्हें बेहतर आजीविका हासिल करने में मदद मिलती है।

कौशल्या सेतु अभियानः एनवाईसीएस 'कौशल्या सेतु अभियान' परियोजना की कार्यान्वयन भागीदार है जिसका उद्देश्य उन छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है जिन्हें एसएससी पास करने में कठिनाई होती है। इस परियोजना का उद्देश्य महाराष्ट्र में हाई स्कूल ड्रॉप आउट 24,332 छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह परियोजना महाराष्ट्र के 34 जिलों में 111 प्रशिक्षण केंद्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

आरपीएल प्रोजेक्टः यह अनौपचारिक शिक्षा या काम के माध्यम से सीखने को मान्यता प्रदान करने के लिए एक मंच है, ताकि शिक्षा के औपचारिक स्तरों के समान स्वीकृति मिल सके। एनवाईसीएस ने टैक्सी, ऑटो रिक्शा और वाणिज्यिक वाहनों के ओला एवं अन्य स्थानीय ड्राइवरों सहित 6,000 ड्राइवरों का प्रशिक्षण और मूल्यांकन पूरा कर लिया है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के पांच शहरों लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और नोएडा में कार्यान्वित की गई है। इसके तहत 1,500 से अधिक उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।

कौशल साथीः एनवाईसीएस ने कौशल साथी की पहल की है। इसमें उम्मीदवारों को अखिल भारतीय स्तर पर गुणात्मक मानकों के साथ मनोवैज्ञानिक परीक्षण और कुशल परामर्श के माध्यम से परामर्श दिया जाता है ताकि कौशल के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके और युवा अपने करियर का सही रास्ता चुन सकें। इसके तहत पांच महीनों में विभिन्न राज्यों में 1 लाख युवाओं का करियर काउंसलिंग किया गया है।

सहकारी बैंकों पर बढ़ा भरोसा

सहकारी बैंकों की जमा और संपत्तियों में वृद्धि, शुद्ध लाभ भी बढ़ा

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 से आया बड़ा बदलाव

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 संसद के बजट सत्र में पारित

युवा सहकार टीम

सहकारी बैंकों में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को रोकने, उनके प्रभावी विनियमन और प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का असर दिखने लगा है। खासकर, अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए जो पहल की गई उससे सहकारी बैंकों पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति पर वित्त मंत्रालय की ओर से संसद में पेश भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और नाबार्ड के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि बेहतर विनियमन और प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में जो संशोधन किए गए उसकी बदौलत सहकारी बैंकों के जमा और संपत्तियों में न सिर्फ वृद्धि हुई है, बल्कि उनका शुद्ध लाभ भी बढ़ा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय द्वारा 'सहकारिता में सहकार' के सिद्धांत को लागू करने का फायदा भी इन बैंकों को मिल रहा है। इसके तहत सहकारी समितियों के लिए सहकारी बैंकों में खाता खोलना अनिवार्य किया गया है।

संसद में पेश आरबीआई और नाबार्ड के आंकड़ों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2024 तक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के पास कुल 7,20,141 करोड़ रुपये की संपत्ति और 5,59,954 करोड़ रुपये की कुल जमा राशि थी। इससे उन्हें 4,130 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। उनका शुद्ध एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) भी घटकर 3.7 प्रतिशत पर आ गया। इसी तरह, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) की कुल संपत्ति इस दौरान 4,88,266 करोड़ रुपये रही जिसमें कुल जमा 2,56,819 करोड़ रुपये थी। एसीटीसीबी को 2,691 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ और एनपीए 2 प्रतिशत पर सिमट

गया। जहां तक जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) की बात है, तो उन्होंने इस दौरान 1,894 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। उनकी कुल संपत्ति 7,65,577 करोड़ रुपये और कुल जमा राशि 4,76,610 करोड़ रुपये रही। इनका शुद्ध एनपीए 3.4 प्रतिशत रहा।

इन कदमों ने बढ़ाया भरोसा

सहकारी बैंकों को नियमों का अनुपालन करने और उनके कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से आरबीआई के दायरे में लाया गया। पहले ये बैंक राज्यों के कानूनों से संचालित होते थे जिसकी वजह से इन पर किसी एक का प्रभावी नियंत्रण नहीं था। बैंकिंग कानून में संशोधन के माध्यम से प्रबंधन, पूंजी और पुनर्निर्माण जैसे क्षेत्रों में अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए। शहरी सहकारी बैंकों के लिए ये प्रावधान 26 जून, 2020 से लागू हैं। इसी तरह, धोखाधड़ी और अनियमितताओं से निपटने के लिए आरबीआई ने धोखाधड़ी प्रबंधन पर मास्टर निर्देश (2024) जारी किया है जो प्रारंभिक चेतावनी तंत्र, धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग और कर्मचारियों की जवाबदेही पर केंद्रित है। इसके अलावा, त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा वित्तीय रूप से कमजोर यूसीबी के लिए समय पर उपचारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करता है। जमाकताओं के धन की सुरक्षा के लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) के माध्यम से जमा बीमा लागू किया गया और रिजर्व बैंक द्वारा जागरूकता अभियान चलाकर ग्राहकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचने की जानकारी दी गई।

इसके अतिरिक्त, नाबार्ड ने धोखाधड़ी रिपोर्टिंग दिशानिर्देश जारी किए हैं इसमें सहकारी बैंकों को वित्तीय अनियमितताओं की सूचना कानून प्रवर्तन एजेंसियों को त्वरित कार्यवाही के लिए देने का निर्देश दिए गए हैं। इनसे इन बैंकों में भ्रष्टाचार पर काबू पाने, गड़बड़ी और धोखाधड़ी रोकने में काफी सफलता मिली है। सहकारी बैंक भी सहकारी संस्था ही होती है, इसलिए बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 में भी संशोधन किया गया है जिससे इन बैंकों में प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है। जमाकर्ताओं की शिकायतों को निपटाने के लिए एक सहकारी लोकपाल नियुक्त किया गया है। साथ ही, सहकारी चुनाव प्राधिकरण का गठन किया गया है।■

10 साल होगा निदेशकों का कार्यकाल

सहकारी बैंकों में प्रशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से अभी हाल ही में समाप्त हुए बजट सत्र में संसद ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया है। इसके माध्यम से सहकारी बैंकों के निदेशकों का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, यह प्रावधान भी किया गया है कि किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के सामान्य निदेशक एक साथ कई बैंकों या वित्तीय संस्थानों के निदेशक नहीं रह सकते हैं। इसके माध्यम से उनकी जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस विधेयक पर संसद में हुई चर्चा के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वाणिज्यिक बैंकों में निदेशक आठ साल तक सेवा करते हैं, जबकि सहकारी बैंकों में पहले यह सीमा पांच साल थी। संविधान में उनके लिए दस साल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। बैंकिंग कानून में संशोधन के माध्यम से उनके कार्यकाल को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि निदेशकों को उनके संवैधानिक कार्यकाल से वंचित नहीं किया जाएगा।

बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, 2024 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934

और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 सहित पांच बैंकिंग कानूनों को प्रभावित करता है। इसमें केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशकों को राज्य सहकारी बैंकों के बोर्ड में काम करने की अनुमति देने का प्रावधान भी किया गया है। बैंकों को अपने ऑडिटरों के पारिश्रमिक का निर्धारण करने में अब पहले से अधिक छूट दी गई है।

इस विधेयक में बैंक खाताधारकों को अधिकतम चार व्यक्तियों को नॉमिनी बनाने की भी अनुमति दी गई है, बैंकिंग नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह बदलाव उन जमाकर्ताओं को ध्यान में रखकर किया गया है जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक है। अधिक सदस्य होने के कारण खाताधारक की मृत्यु के बाद उनमें आपसी झगड़ा होता था जिससे बैंकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। नए प्रावधान से यह मुश्किल दूर होने की उम्मीद है।

सहकारी बैंकों को नियमों का अनुपालन करने और उनके कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के दायरे में लाया गया।

यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही कोऑपरेटिव से जुड़ेंगे युवा

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, 2025 पारित हो गया। इसके साथ ही देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी बनाने का रास्ता साफ हो गया। सहकारी शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए यह बहुत बड़ा सुधार है। सहकारिता क्षेत्र में शिक्षण के लिए अभी बहुत सीमित व्यवस्था है। अब युवा इस क्षेत्र में भी डिप्लोमा, डिग्री, पीएचडी, मैनेजमेंट आदि कोर्स कर सकेंगे और अपना करियर बना सकेंगे। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री **मुरलीधर मोहोल** से इस यूनिवर्सिटी की सार्थकता और व्यापकता सहित सहकारिता क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर **एसपी सिंह** और **अभिषेक राजा** ने लंबी बातचीत की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंशः

देश की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाने को संसद की मंजूरी मिल गई है। इसके पीछे क्या सोच है और इससे कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या नया होने वाला है?

देश में इस समय 8.40 लाख सहकारी समितियां हैं जिनके 30 करोड़ सदस्य हैं और उनमें 40 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं। देश के सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का निर्णय लिया जिसकी जिम्मेदारी श्री अमित शाह को दी गई। सहकारिता मंत्रालय ने अपने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में सहकारिता क्षेत्र में व्यापक सुधार के लिए बहुत सारी पहल की हैं। यूनिवर्सिटी बनाने की बात अमित भाई के दिमाग में आई। 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाना होगा और इसके लिए सहकारिता एक बड़ा माध्यम है। देश में सहकारिता का इतना बड़ा स्वरूप है, तो उसका एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी होना चाहिए। डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आदि अलग-अलग तरह के कोर्स के माध्यम से स्किल्ड मैनपावर तैयार किए जाने चाहिए। एक अनुमान है कि सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करने के लिए अगले कुछ वर्षों में सहकारिता क्षेत्र को 17 लाख स्किल्ड मैनपावर की जरूरत पड़ेगी। इसे ध्यान में रखते हुए यही सोच थी कि अगर हमें और आगे जाना है, तो भविष्य की मांग को पूरा करने की तैयारी आज से ही करनी होगी। चाहे वह टेक्नोलॉजी हो, शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो, सभी में काम करने के लिए ही यूनिवर्सिटी का प्रावधान किया गया। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, 2025 को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया है जो सहकारिता क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि है।

त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, विभिन्न राज्यों के कोऑपरेटिव शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान इससे कैसे जुड़ेंगे?

यह यूनिवर्सिटी हब और स्कोप मॉडल पर पूरे देश के लिए काम करेगी। इस मॉडल के माध्यम से किसी भी राज्य में सहकारिता से जुड़े शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकते हैं, वहां के शिक्षण-प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट इससे एफिलिएशन ले सकते हैं। इसके अलवा, इसकी खासियत यह भी होगी कि जिस राज्य में इंस्टीट्यूट होगा वहां की प्रांतीय भाषा में पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध होगी। पूरे देश के सहकारिता क्षेत्र में किसी भी पद के लिए, चाहे पैक्स का सचिव हो या अपेक्स बैंक के एमडी हों, सभी तरह के पद के लिए युवाओं को तैयार करना है, तो उसके लिए अलग-अलग कोर्स एवं डिग्री हों, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। साथ ही, वर्तमान में कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम कर रहे पैक्स के सचिव से लेकर अपैक्स बैंक के एमडी तक सभी को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से सभी के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। सहकारिता क्षेत्र बहुत विशाल है और यह समाज के सभी अंगों से जुड़ा है। सभी को अच्छी ट्रेनिंग देकर सहकारी आंदोलन को और मजबूत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की सहकार से समृद्धि की जो परिकल्पना है उसे साकार करने के लिए यूनिवर्सिटी के माध्यम से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। स्किल्ड मैनपावर का सृजन करने के अलावा कोऑपरेटिव के स्पिरिट को बढ़ावा देने में भी हम सक्षम होंगे। इसके बहुत सारे आयाम हैं जिसे यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरा कर पाएंगे।

सहकारिता क्षेत्र में युवाओं और महिलाओं के लिए कितनी संभावनाएं हैं, यूनिवर्सिटी बनाने के अलावा उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए और क्या किया जा रहा है?

मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ही एक ऐसा माध्यम है जो युवाओं को कोऑपरेटिव से जोड़ सकता है। आज अगर आप देखें तो किसी भी क्षेत्र में नौकरी पाने या बिजनेस खड़ा करने के लिए कोई न कोई कोर्स उपलब्ध है और उनकी शिक्षा दी जा रही है। इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, मैनेजमेंट है या अन्य कोई भी क्षेत्र, उनके लिए कॉलेज एवं इंस्टीट्यूट हैं। युवाओं को पता है कि किन संस्थानों से पढ़ने के बाद उन्हें किन क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। ऐसी कोई व्यवस्था कोऑपरेटिव में नहीं थी। यूनिवर्सिटी के माध्यम से देश की कोऑपरेटिव स्पिरिट को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं की लीडरशिप तैयार के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। यही एक नींव है जिससे जुड़ने के बाद वे इस क्षेत्र में कुछ न कुछ काम कर सकेंगे। इससे उनका भविष्य बहुत सुरक्षित हो जाएगा।

इस यूनिवर्सिटी में कब से पढ़ाई शुरू हो पाएगी?

हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द यहां पढ़ाई और प्रशिक्षण शुरू हो जाए। आणंद के इरमा में सब स्ट्रक्चर तैयार है। वहां पर फैकेल्टी भी तैयार हैं और गैर शैक्षणिक कर्मचारी भी तैयार हैं। बहुत जल्द हम यूनिवर्सिटी शुरू कर सकते हैं और उसके बाद पूरे देश में उसका विस्तार भी हो जाएगा।

कोऑपरेटिव सेक्टर में भ्रष्टाचार का एक लंबा इतिहास रहा है, कई बैंकों में घोटाले हुए और आज भी हो रहे हैं जिससे लोगों का भरोसा इन पर

से उठ गया। इन बैंकों को कैसे मजबूत करेंगे और लोगों का भरोसा बहाल करने के लिए क्या कर रहे हैं?

सहकारिता के मूल स्वरूप को अगर देखें तो यह पूरा क्षेत्र लोगों के विश्वास पर चलता है। जितना आप लोगों का विश्वास प्राप्त करेंगे, सहकारिता क्षेत्र को ज्यादा ताकत दे सकते हैं। लोगों का विश्वास प्राप्त करने के लिए कोऑपरेटिव सोसायटी को अच्छी तरह से चलाना चाहिए। मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो स्किल्ड मैनपावर आएगा उससे व्यापक सुधार होगा। आज कई सोसायटी में कार्य क्षमता की कमी है, प्रबंधन में अनियमितता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग कम है। ऐसी बहुत सी दिक्कतें हैं जिससे उनके कार्य में पारदर्शिता नहीं है। इसका समाधान हमने यह निकाला है कि सभी पैक्स का कंप्युटराइजेशन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म हो जाएगा क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही काम करना है जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं रहेगा। यह सब होने के बाद सहकारिता क्षेत्र को अच्छी दिशा मिलेगी। दूसरा, बैंकों के बारे में जो सवाल आपने पूछा, अभी नाबार्ड के माध्यम से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की तो मदद की जाती है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की मदद की कोई संस्था ही नहीं थी। अमित भाई ने इनकी मदद के लिए एक अंब्रेला संगठन राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त विकास निगम (एनयूसीडीएफसी) का गठन किया जो सहकारी बैंकों के लिए एक नियामक की तरह काम करेगा। यह न सिर्फ उनकी आर्थिक रूप से सहायता करेगा, बल्कि उन्हें तकनीकी एवं बुनियादी सहायता देगा और उनकी निगरानी भी करेगा। इससे सहकारी बैंकों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र को काफी फायदा मिलेगा। सहकारी बैंकों में सुधार के लिए सहकारिता मंत्रालय ने और भी कई पहलें की हैं और उन्हें सामान्य बैंकों की तरह सेवाएं देने लायक बनाने के लिए कई नए रास्ते खोले हैं। ये कदम लोगों का टूटा भरोसा बहाल करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होंगे।

> **सभी पैक्स का कंप्युटराइजेशन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इससे भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म हो जाएगा क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही काम करना है जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से भ्रष्टाचार का मामला ही नहीं रहेगा। यह सब होने के बाद सहकारिता क्षेत्र को अच्छी दिशा मिलेगी।**

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर क्या-क्या किया जा रहा है?

पूरे देश में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष मनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने साल भर की एक रूपरेखा तैयार की है ताकि सहकारिता को लेकर जागरूकता बढ़े और इस आंदोलन को मजबूती मिले। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और इसका आधिकारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में किया। यह भारतीय सहकारिता के लिए बड़े सम्मान की बात है। अलग-अलग तरह से इस वर्ष को मनाया जा रहा है। सहकारी आंदोलन को हम किस-किस माध्यम से और सक्षम एवं समृद्ध बना सकते हैं, इस पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। सहकारिता का प्रचार-प्रसार आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसके लिए देश की सभी 8.40 लाख सहकारी समितियों को साल भर कोई न कोई कार्यक्रम करने को कहा गया है ताकि जागरूकता बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। इसके माध्यम से सहकारी आंदोलन को एक नई दिशा और ताकत मिलेगी। भारतीय सहकारिता को और सशक्त बनाने का यह अच्छा अवसर है।■

पीएम इंटर्नशिप: ऐप से भी आवेदन

युवा सहकार टीम

देश के एक करोड़ युवाओं को अगले पांच वर्ष में टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर देने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए आवेदन करना अब और आसान हो गया है। इसके लिए पहले पीएम इंटर्नशिप पोर्टल लॉन्च किया गया था जिस पर इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना की बढ़ती लोकप्रियता और आवेदकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आवेदन को और आसान बनाने के लिए अब इसका ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। पीएम इंटर्नशिप ऐप पर ही आवेदन के साथ-साथ योजना से जुड़ी सभी जानकारी हासिल की जा सकती है।

भारत की शीर्ष कंपनियों में 12 महीने की सशुल्क इंटर्नशिप वाली यह योजना 21-24 वर्ष के युवाओं को शुरूआती प्रशिक्षण प्राप्त करने, अनुभव और कौशल हासिल करने का अवसर प्रदान करती है। यह एकेडेमिक और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच की खाई पाटने में मददगार और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने में सहायक है। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए समर्पित इस ऐप को हाल ही में लॉन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीएम इंटर्नशिप योजना में कक्षा में सीखने और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच की खाई को पाटने की क्षमता है जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। उन्होंने उद्योग से इस योजना में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी देश में कुशल कार्यबल को बढ़ावा देते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देगी। कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस अवसर पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पीएमआईएस ऐप की शुरूआत से युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसरों तक पहुंच में काफी वृद्धि होगी।

इस ऐप में साफ डिजाइन और सहज नेविगेशन के साथ सहज इंटरफेस, आधार फेस ऑथेंटिकेशन के जरिये आसान पंजीकरण, सरल नेविगेशन (योग्य उम्मीदवार स्थान के आधार पर अवसरों को छांट सकते हैं), पर्सनल डैशबोर्ड, एक समर्पित सहायता टीम तक पहुंच, उम्मीदवारों को नए अपडेट से अवगत रखने के लिए रीयल टाइम अलर्ट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट में पीएम इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना की शुरूआत में 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ अक्टूबर 2024 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू की गई। पायलट प्रोजेक्ट के पहले चरण (अक्टूबर-दिसंबर 2024) में 25 क्षेत्रों में लगभग 280 कंपनियों द्वारा 745 जिलों में 1.27 लाख से अधिक अवसर प्रदान किए गए। इस दौरान उम्मीदवारों को 82,000 से अधिक ऑफर दिए गए। प्रोजेक्ट का दूसरा चरण जनवरी से मार्च 2025 तक चला जिसमें लगभग 327 कंपनियों ने 735 जिलों में 1.18 लाख से अधिक अवसर (नए और पिछले दौर के खाली अवसर) प्रदान किए।■

पीएम इंटर्नशिप योजना में कक्षा में सीखने और उद्योग की अपेक्षाओं के बीच की खाई को पाटने की क्षमता है जिससे युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ेगी। निर्मला सीतारमण ने उद्योग से इस योजना में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह करते हुए कहा कि उनकी भागीदारी देश में कुशल कार्यबल को बढ़ावा देते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देगी।

बीज अनुसंधान में क्रांति लाएगी इफको

युवा सहकार टीम

कलोल में इफको के बीज अनुसंधान केंद्र का अमित शाह ने किया शिलान्यास

आने वाले समय में यह केंद्र किसानों की समृद्धि बढ़ाने वाला होगा साबित

खाद्यान्न क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इफको की भूमिका रही है महत्वपूर्ण

इफको नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ने पूरे विश्व में भारतीय सहकारिता की जमाई धाक

फर्टिलाइजर क्षेत्र में झंडा बुलंद करने के बाद इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) अब बीज अनुसंधान क्षेत्र में उतरने वाली है। यह केंद्र सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है जिसके तहत भारतीय पारंपरिक एवं मीठे बीजों को संरक्षित करने और भारतीय जलवायु के लिहाज से ज्यादा पैदावार वाले नए बीजों का अनुसंधान एवं उत्पादन करने का कदम उठाया गया है। इफको का पहला बीज अनुसंधान केंद्र गुजरात के गांधीनगर के कलोल में बनाया जाएगा। यहीं पर इफको का पहला फर्टिलाइजर प्लांट स्थित है। इसी प्लांट के परिसर में बीज अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। प्लांट के 50 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस केंद्र का शिलान्यास किया।

दरअसल, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय पारंपरिक एवं मीठे बीजों के संरक्षण एवं नए बीजों के अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई सहकारी समिति भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड (बीबीएसएल) का गठन किया है। इसके पांच प्रमोटरों में इफको भी शामिल है। भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड के अन्य प्रमोटरों में कृभको, नैफेड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) शामिल हैं। सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारी का निर्वहन करने के तहत इफको अब बीज अनुसंधान क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के अपने लंबे अनुभवों का लाभ उठाएगी।

बीज अनुसंधान केंद्र के शिलान्यास के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा, 'इफको का रिकार्ड है कि जो भी काम इसने हाथ में लिया है उसे तार्किक अंत तक पहुंचाया है। यह बीज अनुसंधान केंद्र भी हमारी जमीन में उत्पादकता बढ़ाएगा, उत्पाद को पोषक बनाएगा, कम पानी और कम खाद का उपयोग हो, बीजों में इस प्रकार का सुधार करेगा। साथ ही, सदियों पुराने बीजों के संरक्षण का काम भी यह केंद्र करेगा।' उन्होंने कहा कि 50 वर्ष पहले जब इफको की नींव डाली गई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि उसका यह सफर यहां तक

पहुंचेगा। इसी प्रकार, आज जब बीज अनुसंधान केंद्र की नींव रखी गई है तब यह केंद्र भी किसानों की समृद्धि को बढ़ाने वाला साबित होगा।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री के अनुसार, इफको की 50 वर्ष की यात्रा यह दिखाती है कि जब कोऑपरेटिव और कॉरपोरेट संस्कार मिलकर काम करते हैं तो कैसे अद्भुत परिणाम मिलते हैं। इफको ने रिसर्च डेवलपमेंट, मार्केटिंग, ब्राडिंग और घर-घर तक पहुंच बनाने से संबंधित सभी काम बेहद कुशलता के साथ किए हैं। आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, तो इसमें इफको की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इफको ने देश के किसानों को फर्टिलाइजर के साथ जोड़ा और फिर फर्टिलाइजर को कोऑपरेटिव से जोड़ा। 50 वर्ष पहले जब इफको के कलोल के कारखाने का भूमिपूजन हुआ उस समय फर्टिलाइजर के क्षेत्र में इसे बड़ी क्रांति माना गया था। बदलते समय के साथ इफको ने नैनो तकनीक के माध्यम से नैनो यूरिया (तरल) और नैनो डीएपी (तरल) आदि के लिए रिसर्च और प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाया।

इफको के नैनो यूरिया और नैनो डीएपी ने पूरे विश्व में भारतीय सहकारिता क्षेत्र की धाक जमाई है। इन दोनों लिक्विड फर्टिलाइजर का निर्यात 40 देशों में किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी इस सहकारी संस्था ने अपनी क्षमता बढ़ाने के साथ किसानों के खेत तक भी पहुंच बढ़ाई है और शोध एवं अनुसंधान के माध्यम से प्रयोगशाला में होने वाले प्रयोगों को जमीन तक पहुंचाया है। पिछले 50 साल में केमिकल फर्टिलाइजर से नैनो फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर तक की यात्रा इफको के नेतृत्व में हुई है। जब इफको की स्थापना हुई थी तब देश का ध्यान फर्टिलाइजर के ज्यादा उत्पादन पर केंद्रित था क्योंकि तब इनका ज्यादातर आयात होता था। अब भारत का ध्यान टार्गेटेड और कंट्रोल प्रोडक्शन पर है, जिससे पोषक तत्व भी मिलेंगे और जमीन भी खराब नहीं होगी। पहले हाई कॉस्ट और लो एफिशिएंसी और अब लो कॉस्ट और हाई एफिशिएंसी तक पहुंचने का काम इफको ने किया है। इफको के कांडला, कलोल, फूलपुर, आंवला और पारादीप प्लांट में फर्टिलाइजर का उत्पादन होता है जिसकी बदौलत भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। आज इफको की उत्पादन क्षमता 90 लाख टन, बिक्री 110 लाख टन, टर्नओवर 40 हजार करोड़ रुपये और मुनाफा 3,200 करोड़ रुपये है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि इफको ने अपनी उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ा ली है कि आज पूरी दुनिया में इसके उत्पाद जा रहे हैं। इस सहकारी संगठन के 50 वर्ष हमारी खेती, अनाज उत्पादन, ग्रामीण अर्थतंत्र और किसानों की समृद्धि को समर्पित रहे हैं। इसी प्रकार, इसके आगामी 50 से 100 वर्ष तक की यात्रा खेती को आधुनिक, सबसे ज्यादा उत्पादक बनाकर अपनी जमीन का संरक्षण करने और पर्यावरण को बचाने के उदेश्यों के साथ पूरी होगी।■

यह बीज अनुसंधान केंद्र जमीन की उत्पादकता बढ़ाएगा, उत्पाद को पोषक बनाएगा, कम पानी और कम खाद का उपयोग हो, बीजों में इस प्रकार का सुधार करेगा। साथ ही, सदियों पुराने बीजों के संरक्षण का काम भी यह केंद्र करेगा।

सहकारिता में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर

महिलाओं और युवाओं में स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) विभिन्न योजनाएं चलाता है। इन योजनाओं में स्वयं शक्ति सहकार, नंदिनी सहकार और युवा सहकार जैसी योजनाएं प्रमुख हैं। एनसीडीसी सहकारिता के क्षेत्र में भारत सरकार की विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी भी है।

युवा सहकार टीम

सहकार से समृद्धि और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सहकारी समितियों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए भी यह जरूरी है। सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं और युवाओं में स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिले, इसके लिए केंद्र सरकार हर तरीके से प्रयास कर रही है। खासकर, जब से अलग सहकारिता मंत्रालय बना है, तब से इस प्रयास में तेजी आई है। प्राथमिक सहकारी समितियों (पैक्स) का जो नया मॉडल बायलॉज है उसमें भी महिलाओं और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का कानूनी प्रावधान किया गया है। पैक्स के बोर्ड में महिला निदेशकों की आवश्यकता को अनिवार्य किया गया है। इससे देशभर के एक लाख से अधिक पैक्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और उनके द्वारा निर्णय लेना सुनिश्चित हो रहा है। इसी तरह, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी (एमएससीएस) के बोर्ड में महिलाओं के लिए दो सीटों का आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इससे सहकारी क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का भी मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

महिलाओं और युवाओं में स्वरोजगार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) विभिन्न योजनाएं चलाता है। इन योजनाओं में स्वयं शक्ति सहकार, नंदिनी सहकार और युवा सहकार जैसी योजनाएं प्रमुख हैं। एनसीडीसी सहकारिता के क्षेत्र में भारत सरकार की विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी भी है। यह सहकारी क्षेत्र को वित्तीय मदद देती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, एनसीडीसी ने महिला सहकारी समितियों को पिछले तीन वित्त वर्ष (2022-23, 2023-24 और 2024-25) में 3099.33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

प्रदान की है। इसकी बदौलत इन समितियों को आर्थिक संबल मिला है।

स्वयं शक्ति सहकारः इस योजना का उद्देश्य गरीबों को सस्ती, लागत प्रभावी और विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना, महिला स्वयं सहायता समूहों को सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए पर्याप्त बैंक ऋण तक पहुंच प्रदान करना और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को 3 वर्ष तक के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स), जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी), राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और स्वयं सहायता समूह की संघीय सहकारी समितियां एवं सहकारी संघ एनसीडीसी की वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

नंदिनी सहकारः इस योजना का लक्ष्य महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है और महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमी गतिशीलता का समर्थन करना है। एनसीडीसी की नंदिनी सहकार योजना वित्तीय सहायता, परियोजना निर्माण, सहायता और क्षमता विकास की महिला केंद्रित योजना है। इसका उद्देश्य शहरी आवास को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय मॉडल आधारित गतिविधियों को शुरू करने में महिला सहकारी समितियों की सहायता करना है। इस योजना के उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। यह पहल उद्यम विकास, व्यवसाय योजना, क्षमता निर्माण और ऋण और ब्याज अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता जैसे इनपुट से उद्यमशीलता की गतिशीलता को बढ़ावा देकर महिला सहकारी समितियों का समर्थन करती है। इस योजना के तहत महिला सहकारी समितियों को 5-8 वर्ष की अवधि के लिए सावधि ऋण प्रदान किया जाता है, जिसमें सावधि ऋण पर 2 प्रतिशत तक की ब्याज छूट दी जाती है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता एनसीडीसी को सौंपे गए व्यवसाय योजना आधारित गतिविधि के लिए प्रदान की जाती है। इस योजना से 1.56 करोड़ महिला सदस्यों को लाभ पहुंचा है।

युवा सहकार योजनाः युवा सहकार-सहकारी उद्यम समर्थन और नवाचार योजना एनसीडीसी द्वारा चलाई जाने वाली एक युवा केंद्रित योजना है। इस योजना को युवाओं की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 नवंबर, 2018 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य नए और अभिनव विचारों वाली नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। यह योजना युवा उद्यमी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करती है जो कम से कम 3 महीने से परिचालन में हैं। इस योजना में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कोष की स्थापना की गई है। यह योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र और आकांक्षी जिलों में सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति और

स्वयं शक्ति सहकार योजना का उद्देश्य गरीबों को सस्ती, लागत प्रभावी और विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना, महिला स्वयं सहायता समूहों को सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए पर्याप्त बैंक ऋण तक पहुंच प्रदान करना और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को 3 वर्ष तक के लिए कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाता है।

अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को विशेष ध्यान दिया जाता है।

यह योजना अपना व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसमें 3 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए मानक दर से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर लोन दिया जाता है। साथ ही मूलधन भुगतान पर दो वर्ष की मोहलत भी दी जाती है। एनसीडीसी उन अभ्यर्थियों के लिए परियोजना लागत का 80 प्रतिशत वहन करता है जो विशेष समूह जैसे महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या विकलांग व्यक्ति से संबंधित हैं। जो विशेष श्रेणी में नहीं आते हैं उन्हें कुल परियोजना लागत का 70 प्रतिशत तक सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। एनसीडीसी और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी प्रक्रियाओं का सत्यापन हो जाने के बाद आवेदक www.ncdc.in पोर्टल पर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

युवा सहकार- सहकारी उद्यम समर्थन और नवाचार योजना एनसीडीसी द्वारा चलाई जाने वाली एक युवा केंद्रित योजना है। इस योजना का उद्देश्य नए और अभिनव विचारों वाली नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। यह योजना उन युवा उद्यमी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करती है जो कम से कम 3 महीने से परिचालन में हैं।

सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना: सहकारिता के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एनसीडीसी सहकार मित्र इंटरर्नशिप योजना भी चलाता है। इससे सहकारिता क्षेत्र के स्टार्ट अप और किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) सहित विभिन्न क्षेत्रों के बारे में युवाओं की जानकारी को बेहतर किया जाता है। इस योजना में युवाओं को सफल सहकारी संगठनों की गतिविधियां, संचालन और प्रबंधकीय व्यवस्था आदि की जानकारी दी जाती है। एनसीडीसी का मानना है कि केवल सहकारी शिक्षा ही नहीं, सहकारिता में युवाओं का योगदान को बढ़ाने के लिए प्रायोगिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना होगा। इसी उद्देश्य से सहकार मित्र इंटर्नशिप योजना को शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य सहकारिता में एनसीडीसी की भूमिका, सहकारी व्यापार मॉडल और किसान उत्पादक संगठनों के बारे में युवाओं की समझ को बेहतर करना है। यह योजना कृषि, डेयरी, पशुपालन, पशु चिकित्सा विज्ञान, मत्स्य पालन, बागवानी, कपड़ा, हथकरघा और आईटी जैसे क्षेत्रों में स्नातक पास युवाओं के लिए है। इसके अतिरिक्त कृषि व्यवसाय, सहकारी प्रबंधन, एमकॉम, एमसीए, वित्त, ग्रामीण विकास परियोजना प्रबंधन या संबंधित विषयों में एमबीए करने वालों युवा भी इसके लिए पात्र उम्मीदवार हैं। सहकार मित्र योजना के माध्यम से प्रशिक्षुओं को एनसीडीसी के संचालन का व्यावहारिक अनुभव भी मिलेगा, साथ ही उन्हें व्यवसाय नियोजन और परियोजना विकास में सहकारी समितियों की सहायता भी दी जाएगी। यह कार्यक्रम युवा पेशेवरों को एफपीओ में उद्यमशीलता और नेतृत्व की भूमिकाएं तलाशने और स्टार्टअप सहकारी समितियों के विकास का समर्थन करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

इसके अलावा, एनसीडीसी ने लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान और विकास अकादमी (एलआईएनएसी) के साथ क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से विगत पांच वर्षों (2020-21 से 2024- 25 तक) में व्यवसाय विकास और संपत्ति प्रबंधन, पैक्स में सामान्य प्रबंधन, सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों के शासन और व्यवसाय विकास में महिला निदेशकों की भूमिका,

अकाउंटिंग और बुक कीपिंग जैसे विषयों तथा विभिन्न कार्यक्रमों में कुल 1,370 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया है। इससे 38,179 महिला प्रतिभागियों सहित सहकारी समितियों के लगभग 1,95,567 प्रतिभागी लाभान्वित हुए हैं।

देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय पैक्स को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने पर भी फोकस कर रहा है। इसके लिए पैक्स का कंप्युटराइजेशन कर उसे विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने की मंजूरी दी गई है। पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने के लिए उन्हें डेयरी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीज, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल वितरण, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), उचित मूल्य की दुकानें, सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय संवाददाता गतिविधियों सहित 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियों को करने की मंजूरी दी गई है। अब तक 42,080 पैक्स सीएससी के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि 36,193 पैक्स पीएमकेएसके (प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र) के रूप में काम कर रहे हैं। 22,311 पैक्स उचित मूल्य की दुकानों का संचालन कर रहे हैं।

इनके माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। सरकार ने देश भर की सभी पंचायतों को पैक्स से लैस करने के लिए 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का जो लक्ष्य रखा है, उसका फायदा भी अंततः युवाओं और महिलाओं को मिलेगा जिससे सहकारिता में इनकी भागीदारी बढ़ेगी और इनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। इसके अलावा, सहकारी बैंको को मजबूत बनाने और उनका कारोबार बढ़ाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे भी युवा लाभान्वित हो रहे हैं।■

देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय पैक्स को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने पर भी फोकस कर रहा है। इसके लिए पैक्स का कंप्युटराइजेशन कर उसे विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने की मंजूरी दी गई है।

स्टार्टअप कंपनियों से ज्यादा बेहतर करने की उम्मीद

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चीन से तुलना करते हुए भारतीय स्टार्टअप्स को दिखाया आईना

एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, 3डी मैन्युफैक्चरिंग जैसे डीप टेक स्टार्टअप्स की सीमित संख्या पर जताई चिंता

युवा सहकार टीम

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इस उपलब्धि का श्रेय युवाओं में उद्यमशीलता की भावना और तकनीकी प्रगति को जाता है। भारत के आर्थिक और तकनीकी विकास को गति देने में स्टार्टअप की उभरती भूमिका महत्वपूर्ण है। मगर एआई, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, 3डी मैन्युफैक्चरिंग और अगल पीढ़ी की टेक्नोलॉजी जैसे डीप टेक स्टार्टअप्स की संख्या बहुत सीमित है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण के उद्घाटन मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चीन के स्टार्टअप्स से भारतीय स्टार्टअप्स की तुलना करते हुए उन्हें आईना क्या दिखाया, इसे लेकर देश में नई बहस छिड़ गई। बड़े घरेलू स्टार्टअप्स गोयल पर हमलावर हो गए। हालांकि, उन्होंने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और आश्वासन दिया कि सरकार उन लोगों का समर्थन करेगी जो अपनी स्टार्टअप यात्रा में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने उद्यमियों से शॉर्ट टर्म बिजनेस मॉडल से आगे की सोचने और ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की दिशा में काम करने का आग्रह किया।

पीयूष गोयल ने अपने बयान में जो कहा वह एक सच्चाई है और इस सच्चाई से मुंह मोड़ने का मतलब है अपनी कमजोरियों को दुरुस्त करने की बजाय उन्हें छुपाने पर ध्यान केंद्रित करना। हालांकि, गोयल को जवाब देते हुए स्टार्टअप्स संस्थापकों ने जो कहा वह भी पूरी तरह से सच है। स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के उद्घाटन मौके पर पीयूष गोयल ने अपने संबोधन के दौरान एक स्लाइड दिखाया जिसका शीर्षक था 'भारत बनाम चीनः स्टार्टअप का रियलिटी चेक' (India Vs China: The Startup Reality Check)। इसी की वजह से सारा विवाद खड़ा हुआ। इस स्लाइड में बताया गया कि जहां चीनी स्टार्टअप्स इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे डीप टेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहीं भारतीय स्टार्टअप्स ज्यादातर फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और कंज्यूमर सर्विसेज पर केंद्रित हैं।

उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि चीन के स्टार्टअप्स बैटरी टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर बना रहे हैं जो भविष्य के लिए उन्हें तैयार कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, 'हम

क्या करना चाहते हैं? आइसक्रीम बनाना या सेमीकंडक्टर चिप्स?' उन्होंने खासतौर पर उन स्टार्टअप्स की आलोचना की जो 'फैंसी आइसक्रीम' और 'कुकीज' जैसे प्रीमियम कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। उनका कहना था कि कुछ अरबपतियों के बच्चे 'हेल्दी, ग्लूटेन फ्री, वीगन' जैसे शब्दों और अच्छी पैकेजिंग के साथ इन्हें स्टार्टअप कहते हैं, लेकिन यह दुकानदारी है, न कि असली स्टार्टअप। हमें फैसला करना होगा कि आइसक्रीम बनाना है या सेमिकंडक्टर चिप्स। उन्होंने फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स स्टार्टअप्स (जो मिनटों में डिलीवरी करते हैं) पर निशाना साधते हुए कहा, 'ये बेरोजगार युवाओं को सस्ते श्रमिक बना रहे हैं, ताकि अमीर लोग घर बैठे खाना मंगा सकें। चाइनीज स्टार्टअप्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी टेक्नोलॉजीज के सेक्टर में पूरी दुनिया में डॉमिनेट कर रहे हैं। क्या हम डिलीवरी बॉयज और गर्ल्स बनकर खुश रहेंगे? क्या यही भारत का भविष्य है? दुकानदारी ही करनी है या दुनिया में अपनी पहचान बनानी है?'

वाणिज्य मंत्री द्वारा पूछे गए ये सवाल भारतीय स्टार्टअप्स को रास नहीं आए और विवाद खड़ा हो गया। गोयल पर सबसे पहले हमलावर हुए क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो के सीईओ आदित पालिचा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, 'भारत में उपभोक्ता स्टार्टअप्स की आलोचना करना आसान है, खासतौर से जब आप उनकी तुलना चीन और अमेरिका से कर रहे हों। अगर जेप्टो की बात करें तो इसके जरिये आज भारत में लगभग 1.5 लाख लोग आजीविका कमा रहे हैं और सरकार को मिलने वाले टैक्स में हर साल 1,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का सहयोग कर रही है।' भारत-पे के संस्थापक रहे अशनीर ग्रोवर ने एक्स पर लिखा, 'अगर भारत में किसी को रियलिटी चेक की जरूरत है तो वह राजनेताओं को है। उनके अलावा हर कोई वास्तविकता में जी रहा है। चीन ने भी शुरू में फूड डिलीवरी ऐप बनाए। बाद में वे एआई टेक की तरफ आगे बढ़े। चीन ने जो किया उससे प्रेरित होना अच्छा है। लोगों के लिए नौकरियां पैदा करने वालों

की आलोचना करने से पहले राजनेताओं को भी अगले 20 वर्षों तक 10 प्रतिशत से अधिक आर्थिक विकास दर से आगे बढ़ने की आकांक्षा करनी चाहिए।'

हालांकि, ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल ने उनके समर्थन में कहा, 'स्टार्टअप समुदाय को आत्मचिंतन करना चाहिए कि हम कंज्यूमर टेक कंपनी ही क्यों बना रहे हैं। उद्यमियों को इस पर सोचने की जरूरत है। लाइफस्टाइल से जुड़े ऐप बनाने की बजाय उन्हें नवाचार और भविष्य की तकनीक पर काम करना चाहिए। जैसे कि उन्हें रॉकेट्स, एआई ड्रग्स, ईयूवी मशीन आदि बनाने पर ध्यान देना चाहिए।' नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने इस अवसर पर कहा कि भारत को एआई जैसी अपनी खुद की एडवांस टेक्नोलॉजी बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। साथ ही, देश को टेक्नोलॉजी से जुड़ी प्रगति को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर रहने से भी बचना होगा। भारत को अपनी तकनीकी स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए और ऐसी तकनीकें बनानी चाहिए, जो देश की अनूठी संस्कृति और पहचान को दर्शाती हों। भारत को पश्चिम या किसी अन्य देश का 'तकनीकी उपनिवेश' नहीं बनना चाहिए। इसकी बजाय ऐसे इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो क्विक, एनर्जी एफिशिएंट और लागत प्रभावी हों।

फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स स्टार्टअप्स बेरोजगार युवाओं को सस्ते श्रमिक बना रहे हैं, ताकि अमीर लोग घर बैठे खाना मंगा सकें। चाइनीज स्टार्टअप्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी टेक्नोलॉजीज के सेक्टर में पूरी दुनिया में डॉमिनेट कर रहे हैं। क्या हम डिलीवरी बॉयज और गर्ल्स बनकर खुश रहेंगे? क्या यही भारत का भविष्य है? दुकानदारी ही करनी है या दुनिया में अपनी पहचान बनानी है?

चीन ने भी शुरू में फूड डिलीवरी ऐप बनाए। बाद में वे एआई टेक की तरफ आगे बढ़े। चीन ने जो किया उससे प्रेरित होना अच्छा है। लोगों के लिए नौकरियां पैदा करने वालों की आलोचना करने से पहले राजनेताओं को भी अगले 20 वर्षों तक 10 प्रतिशत से अधिक आर्थिक विकास दर से आगे बढ़ने की आकांक्षा करनी चाहिए।

क्या कहते हैं आंकड़े

वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, कॉरपोरेट डेवलपमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम करने वाले पेशेवरों को बेंगलुरु स्थित कंपनी ट्रैक्सन रिसर्च और डील सोर्सिंग प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। यह ग्लोबल स्टार्टअप डाटा प्लेटफॉर्म है। ट्रैक्सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाईटेक स्टार्टअप्स में कुल वेंचर कैपिटल/प्राइवेट इक्विटी के जरिये निवेश 2023 के 4.06 अरब डॉलर से गिरकर 2024 में 3.55 अरब डॉलर रह गया। यानी एक वर्ष में ही 12.5 प्रतिशत की गिरावट आई है। यह गिरावट लगभग सभी उच्च तकनीकी क्षेत्रों में देखी गई। एआई को लेकर दुनियाभर में निवेश का माहौल गर्म है, लेकिन भारत में 2023 के 1.3 अरब डॉलर के मुकाबले 2024 में यह घटकर 1.2 अरब डॉलर रह गया। डीप टेक सेक्टर दुनिया में वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का नया ठिकाना बन चुका है, लेकिन भारत में यह गिरावट की राह पर है। 2022 में जहां इस सेक्टर में 2.61 अरब डॉलर का निवेश हुआ था, वहीं 2024 में यह घटकर 94.81 करोड़ डॉलर पर आ गया। सेमीकंडक्टर/डिजाइन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में एक साल में करीब 80 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यह 2023 के 13.44 करोड़ डॉलर से घटकर 2024 में सिर्फ 2.8 करोड़ डॉलर रह गई।

यही हाल ईवी सेक्टर का है। इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) क्षेत्र में कभी निवेश की बाढ़ थी। 2022 में इस क्षेत्र में 2 अरब डॉलर और 2023 में 1.5 अरब डॉलर का निवेश हुआ, लेकिन ईवी की गुणवत्ता को लेकर उठते सवालों के चलते अब निवेशकों ने कदम खींच लिए हैं। 2024 में इस क्षेत्र में निवेश 1.2 अरब डॉलर तक सिमट गया। इस दौरान रोबोटिक्स ही एकमात्र ऐसा सेक्टर रहा जिसने 2024 में 8.36 करोड़ डॉलर का निवेश खींचा जो 2023 के मुकाबले तीन गुना ज्यादा है।

पीयूष गोयल द्वारा की गई आलोचना एक चेतावनी है। अगर भारत को 'टेक्नोलॉजी लीडर' बनना है तो स्टार्टअप्स को वास्तविक नवाचार की राह पकड़नी होगी। एआई, सेमीकंडक्टर्स और डीपटेक न केवल आर्थिक, बल्कि रणनीतिक रूप से भी देश के भविष्य के लिए जरूरी हैं। गोयल ने रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, 3डी मैन्युफैक्चरिंग और अगली पीढ़ी की उभरती टेक्नोलॉजी में निवेश की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ये नवाचार 'विकसित भारत 2047' के विजन को साकार करने और भारत को उद्योग और नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। भारतीय निवेशकों को घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने घरेलू पूंजी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करने और दीर्घकालिक आर्थिक लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए स्वदेशी निवेश का मजबूत आधार इसके लिए महत्वपूर्ण है।

स्टार्टअप महाकुंभ भारत के सबसे बड़े नवाचार और उद्यमिता कार्यक्रमों में से एक है। यह स्टार्टअप, निवेशकों, इनक्यूबेटर एवं एक्सेलरेटर्स और कई क्षेत्रों के उद्यमियों सहित भारत के पूरे स्टार्टअप तंत्र को एक साथ लाता है।

स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत करने पर फोकस

युवा सहकार टीम

भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम मौजूद है। इसे और मजबूत बनाने के लिए उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) निजी कंपनियों से लगातार समझौता ज्ञापन (एमओयू) कर रहा है। इसी कड़ी में यस बैंक और किंड्रिल सॉल्यूशंस से एमओयू किया गया है। इसका मकसद नवाचार को प्रोत्साहन देना और देशभर के स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उद्यमियों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करना है। इससे रोजगार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

किंड्रिल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से हुए एमओयू के तहत डिजिटल रूपांतर और जेनेरेटिव एआई समाधानों में किंड्रिल की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर मैन्युफैक्चरिंग और आईटी क्षेत्रों में स्टार्टअप का सहयोग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस साझेदारी के अंतर्गत, स्टार्टअप को मेंटरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग और बाजार पहुंच के माध्यम से सशक्त बनाया जाएगा जिससे वे ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स, बीएफएसआई, तेल व गैस और सरकारी सेवाओं जैसे उद्योगों में उद्यम समाधानों को एकीकृत करने में सक्षम होंगे। डिजिटल उत्पाद, स्टार्टअप, एआई संचालित इनोवेटर्स और उद्यमियों का सहयोग करने के लिए किंड्रिल समर्पित कार्यक्रमों को संस्थागत रूप देगी। किंड्रिल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड अमेरिकी बहुराष्ट्रीय आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर किंड्रिल होल्डिंग्स इंक की अनुषंगी कंपनी है। यह कंपनी सूचना प्रणालियों का डिजाइन, निर्माण, प्रबंधन और विकास करती है। साथ ही, व्यावसायिक सलाहकार सेवाए भी देती है। किंड्रिल होल्डिंग्स दुनिया की सबसे बड़ी आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर और पांचवीं सबसे बड़ी कंसल्टिंग प्रोवाइडर है।

डीपीआईआईटी ने स्टार्टअप इकोसिस्टम में नवाचार को प्रोत्साहन देने और उनके वित्तीय समाधान के लिए किंड्रिल एवं यस बैंक से किया एमओयू

डीपीआईआईटी के संयुक्त सचिव संजीव ने इस एमओयू पर कहा कि यह सहयोग भारत में नवाचार संचालित स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। किंड्रिल की वैश्विक विशेषज्ञता और उद्यम समाधानों का लाभ उठाकर डीपीआईआईटी का लक्ष्य स्टार्टअप्स को उनके परिचालन को बेहतर करने और उद्योगों में तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ाने में मदद करना है।

इसी तरह, निजी क्षेत्र के यस बैंक से हुए एमओयू के माध्यम से डीपीआईआईटी की स्टार्टअप इंडिया पहल और यस बैंक की वित्तीय विशेषज्ञता का लाभ उठाया जाएगा ताकि शुरूआती चरण के उद्यमों के लिए बाजार संपर्क, फंडिंग की उपलब्धता, मार्गदर्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सहायता की सुविधा मिल सके। घरेलू स्टार्टअप को यस बैंक के हेड स्टार्टअप कार्यक्रम से लाभ होगा जो कार्यशील पूंजी, क्रेडिट पहुंच और नकदी प्रवाह प्रबंधन सहित बैंकिंग और वित्तीय समाधान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, उन्हें यस बैंक के व्यापक नेटवर्क, रणनीतिक साझेदारी और उद्योग विशेषज्ञता तक पहुंच मिलेगी जिससे वे परिचालन बढ़ाने और प्रभावी ढंग से निवेश आकर्षित करने में सक्षम होंगे। भारत का मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम एक परिवर्तनकारी मोड़ पर है। इस तरह की साझेदारी नवाचार आधारित विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

इस समझौता ज्ञापन पर डीपीआईआईटी निदेशक डॉ. सुमीत जारंगल और यस बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख रोहित अनेजा ने वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। यह सहयोग भारत में एक मजबूत और आत्मनिर्भर स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

एनवाईसीएस ने अंकिता की उम्मीदों को किया रौशन

> **एनवाईसीएस की उरुली कांचन शाखा से मिले 2 लाख रुपये के लोन की सहायता से अंकिता ने अपनी खुद की सिलाई-कढ़ाई की दुकान खोली। इसके अलावा, उसने फैब्रिक पेंटिंग क्लासेस भी शुरू किया जिससे उसके सपने साकार हुए। आज उसकी दुकान न केवल स्थानीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है, बल्कि कढ़ाई और फैब्रिक पेंटिंग सीखने के लिए उत्सुक युवतियों और महिलाओं के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र भी बन गई है।**

युवा सहकार टीम

नेशनल युवा कोऑपरेटिव सोसायटी (एनवाईसीएस) पिछले 20 वर्ष से देशभर के युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित करने और उद्यमी बनने के उनके सपनों को साकार करने में मददगार बन रही है। बुलंद हौसलों मगर सीमित संसाधन वाले युवाओं का आर्थिक सशक्तिकरण कर यह सहकारी संस्था उनकी उम्मीदों को रौशन कर रही है। अब तक हजारों युवक और युवतियां एनवाईसीएस की सहायता से सफलता की कहानी गढ़ने में कामयाब हुए हैं। ऐसे सफल युवक-युवतियों की कहानी 'युवा सहकार' पत्रिका के हर अंक में छापी जाती है। इस बार की सक्सेस स्टोरी अंकिता अजिंक्य कंचन की है जिन्होंने अपने जुनून को सफल व्यवसाय में तब्दील कर दिया।

महाराष्ट्र के पुणे जिले में आकांक्षाओं से भरा एक छोटा शहर उरुली कांचन स्थित है। यहां रहने वाली अंकिता अजिंक्य कंचन सिलाई और कढ़ाई में निपुण है। उसने अपने इस कौशल को व्यवसाय में परिवर्तित करने और इसके माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता का सपना देखा था, लेकिन सीमित संसाधनों की वजह से वह अपने सपने को हकीकत में नहीं बदल पा रही थी। इस मुश्किल परिस्थिति में जब वह एनवाईसीएस के संपर्क में आई तो संस्था ने उसे आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया जिसकी बदौलत उसने अपने जुनून को एक सफल व्यवसाय में बदल दिया। एनवाईसीएस की उरुली कांचन शाखा से मिले 2 लाख रुपये के लोन की सहायता से अंकिता ने अपनी खुद की सिलाई-कढ़ाई की दुकान खोली। इसके अलावा, उसने फैब्रिक पेंटिंग क्लासेस भी शुरू किया जिससे उसके सपने साकार हुए।

एनवाईसीएस के वित्तीय समर्थन से वह उच्च गुणवत्ता वाली सिलाई मशीनों, कढ़ाई सामग्री और कार्यशाला स्थान में निवेश करने में सक्षम हुई। आज उसकी दुकान न केवल स्थानीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करती है, बल्कि कढ़ाई और फैब्रिक पेंटिंग सीखने के लिए उत्सुक युवतियों और महिलाओं के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र भी बन गई है।

अंकिता की सफलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह उन जैसी अन्य युवतियों और महिलाओं के लिए प्रेरणा है। अपने प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से वह दूसरों को मूल्यवान कौशल प्रदान कर रही हैं जो उन्हें आजीविका के स्रोत उपलब्ध कराने और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। अंकिता की सफलता की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कैसे माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा मिल सकता है और सकारात्मक बदलाव से सीमित संसाधन वालों का उत्थान हो सकता है। एनवाईसीएस का अंकिता कंचन जैसी महिला उद्यमियों का समर्थन करना यह साबित करता है कि सही वित्तीय सहायता से सपने वास्तविकता बन सकते हैं। ■

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
IFFCO KISAN DRONE
असरदार जोड़ी
नैनो यूरिया प्लस
सागरिका
नैनो डी ए पी
IFFCO
NANO UREA PLUS
सागरिका
SAGARIKA
100% प्राकृतिक समुद्री उत्पाद
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
NANO DAP
(8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड
इफको सदन, सी-1, डिस्ट्रिक सेंटर, साकेत प्लेस, नई दिल्ली-110017, भारत
फोन नंबर- 91-11-26510001, 91-11-42592626, वेबसाइट www.iffco.coop
इफको नैनो उर्वरकों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया स्कैन करें"

National Yuva Co-operative Society Limited

NYCS

Empowering Financial Independence

Our Services

Loans: Small, medium, and large loans at highly competitive interest rates, catering to the diverse financial needs of our members.
Deposits: Attractive interest rates, with special benefits for senior citizens and women.
Simplified Process: Our streamlined application process and flexible terms ensure that financial assistance is always within reach.

Our Reach

- Presence in All States & Union Territories
- 37 Branches Nationwide
- 600+ Districts Served by Our Representatives
- Central Administration Office (CAO) in Pune, Led by Senior Banking & Finance Professionals

Why Choose NYCS Ltd.?

- **Trusted Expertise** – Over 20 years in financial services.
- **Nationwide Presence** – A rapidly growing network.
- **Member-Focused** – Tailored financial solutions.
- **Youth Empowerment** – Supporting young entrepreneurs.

Contact Us

209, 2nd Floor, A2B,
Vardhman Janak Market,
Janakpuri, New Delhi-58
+91 9205595944
011-45096652/40153681
nycs.ltd@gmail.com
www.nycsltd.com

Together, let's build a brighter financial future!